राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक : 21.08.2017
स्थान – होटल बी. एन. आर, चाणक्य, रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के 60वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त
Minutes of the 60th Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 60वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन दिनांक 21.08.2017 को होटल बी.एन.आर, चाणक्य, रांची में किया गया | बैठक का आरम्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के महाप्रबंधक श्री प्रसाद जोशी द्वारा सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत संबोधन से हुआ | श्री जोशी ने झारखण्ड सरकार को SHGs के documentation के लिए stamp duty समाप्त करने का निर्णय लिये जाने पर विशेष रूप से धन्यवाद किया एवं सभी बैंको से वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि करने की अपील की ताकि वर्ष के अंतिम महीनो में लक्ष्य प्राप्ति की हड़बड़ी में गलत financing से बचा जा सके | तत्पश्चात मंच पर आसीन झारखंड राज्य के अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त श्री अमित खरे ; संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री मदनेश कुमार मिश्रा ; प्रधान सचिव, परिवहन, झारखंड सरकार, श्री के. के. खंडेलवाल ; सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, श्री अविनाश कुमार ; सचिव वित्त-सह-योजना, झारखंड सरकार, श्री सतेन्द्र सिंह; सचिव, कृषि, झारखंड सरकार, श्रीमती पूजा सिंघल ; क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक, श्री पेट्रिक बरला ; मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री एस. मंडल एवं महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री बी. के. दास का पुष्पगुच्छ दे कर स्वागत किया गया|

बैठक में उपरोक्त सम्मानित अतिथियों के अलावे श्री एस के मुखर्जी, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया; श्री एस. आर. जेना, महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक; श्री जी.आर. पडलकर, महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया; झारखण्ड सरकार के अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी; झारखण्ड राज्य स्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख; झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक एवं विभिन्न बैंकों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे ।

स्वागत कार्यक्रम के पश्चात प्रधान सचिव, परिवहन, झारखंड सरकार, श्री के. के. खंडेलवाल को बैठक को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। अपने सम्बोधन मे श्री खंडेलवाल ने ग्रामीण क्षेत्र मे परिवहन की समुचित एवं सुविधा जनक व्यवस्था नहीं होने और इसे दूर करने के लिए इस दिशा मे राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों, खासकर उनके विभाग द्वारा शीघ्र रूट परमिट देने की बात का जिक्र किया। उन्होंने बैंकों से स्टैंड – अप इंडिया कार्यक्रम के तहत इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऋण देने का अनुरोध किया ।

इसके पश्चात सचिव, ग्रामीण विकास श्री अविनाश कुमार ने अपने सम्बोधन मे RBI के नवीनतम circular, जिसमे SHGs के लिए 5 साल और 5 लाख रु तक के ऋण documentation की चर्चा है, को बैंकों द्वारा निचले स्तर तक पहुँचाने का जिक्र करते हुए कहा कि बैंकों के पास पड़े SHGs के लंबित आवेदनो का शीघ्र निपटारा किया जाये | उन्होंने PMAY के लाभुकों को सरकार द्वारा दिये जा रहे राशि में से ऋण कटौती किये जाने एवं कुछ जिलों यथा-बोकारो, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, खूंटी, गिरिडीह एवं साहेबगंज में जन धन खातों को सामान्य खातों में परिवर्तित नहीं किये जाने का मामला भी उठाया | उन्होंने सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे liquor shop में cash collection के लिए बैंको से विचार करने का अनुरोध किया |

इसके पश्चात सचिव, कृषि, श्रीमती पूजा सिंघल ने अपने वक्तव्य में राज्य में PMFBY के अंतर्गत loanee farmers की कम संख्या पर चिंता जाहिर की | उन्होंने राज्य में KCC के Rupay कार्ड में conversion पर संतोष जताया परंतू गिरिडीह और रामगढ जिलों में conversion के कम होने के कारण वहाँ के LDMs से विशेष ध्यान देने की बात की | उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा राज्य में बैंको द्वारा किसानों से जबरन ऋण वसूली किये जाने से संबंधित मुद्दों का दुष्प्रचार किया जा रहा है जिसके लिए बैंको को सतर्क रहने की आवश्यकता है | इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग network को बढ़ाये जाने एवं अधिक से अधिक कृषि term लोन देने की भी बात कही | उन्होंने बैंको से कृषि कार्य के लिए दिये जाने वाले ऋण का कृषि कार्य में ही उपयोग हो, ऐसा सुनिश्चित करने को कहा | इसी कड़ी मे BOI के महाप्रबंधक श्री एस के मुखर्जी ने भी बैंको द्वारा समुचित मात्रा मे कृषि term लोन नहीं दिये जाने पर चिंता जाहीर की |

श्री मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने सम्बोधन मे झारखंड सरकार के कई विभागों के सचिवों की उपस्थिती पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य मे अब "Momentum Jharkhand" का असर दिखाई पड़ने लगा है | उन्होने बैंको द्वारा प्रथम तिमाही मे हुई उपलब्धियों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि बैंको को राज्य मे आर्थिक गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए ताकि "Momentum Jharkhand" के तहत सँजोये गए वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके | उन्होने सभी बैंको से 10 प्रतिशत शाखाओं मे आधार enrollment की सुविधा

31.08.2017 तक दिये जाने एवं 31.12.2017 तक आधार authentication का कार्य पूर्ण कर लिए जाने की बात कही | स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना मे borrower द्वारा 25% margin contribution पर विचार किए जाने की बात उन्होने की | उन्होने झारखंड मे KCC कार्ड के rupay कार्ड मे coversion पर संतोष जताया और साथ ही इसे अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया | उन्होने LWE क्षेत्रों मे ज्यादा से ज्यादा बैंक शाखाएँ खोले जाने पर ज़ोर दिया | उन्होने कृषि क्षेत्र मे कम ऋण दिये जाने की बात पर कहा कि चूंकि कृषि क्षेत्र मे allied activities को भी मुद्रा योजना मे शामिल कर लिया गया है, अतः बैंको को मुद्रा योजना मे ज्यादा से ज्यादा कृषि ऋण देना सुनिश्चित करना चाहिए | उन्होने झारखंड मे विमुद्रीकरण के पश्चात digital transaction मे हुई वृद्धि और नगदी की किल्लत दूर होने के बाद पुनः इसमे आई कमी की चर्चा करते हुए कहा कि digital transaction को बढ़ावा देने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए | साथ ही उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा BC को नियुक्त कर और existing BCs को activate कर उनके through digital transaction को बढ़ावा दिया जाना चाहिए | उन्होने झारखंड मे शिक्षा ऋण कि उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया और साथ ही विद्या लक्ष्मी पोर्टल के समुचित उपयोग की बात की | उन्होने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे दिये गए ऋण मे कमी आने पर असंतोष प्रकट किया और इसमे अपेक्षित सुधार लाने की अपील की | उन्होने DCC की मीटिंग मे सांसदों को बुलाने की भी बात कही और RBI से इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया |

अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त श्री अमित खरे ने अपने सम्बोधन मे बैंको के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य मे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिस नए भारत कि परिकल्पना की जा रही है, उसे झारखंड राज्य मे भी साकार करने हेतु बैंको को और प्रयास करने की आवश्यकता है | उन्होने आगामी 17.09.2017 को रांची मे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "गरीब कल्याण मेला" का आयोजन किए जाने की बात बताई जिसमे दक्षिणी एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान (जमशेदपुर, चाईबासा, सराईकेला) एवं हजारीबाग के borrowers को एकत्रित कर हर प्रकार के ऋण का वितरण किए जाने का लक्ष्य है | इसके लिए उन्होने सभी बैंको को अभी से ही समुचित तैयारी करने का निर्देश दिया | उन्होने झारखंड सरकार द्वारा ST/SC/OBC के विद्यार्थियों के लिए रु 7.50 लाख से अधिक के शिक्षा ऋण के लिए चलाये जा रहे guarantee scheme का जिक्र करते हुए सभी बैंको से ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ऋण दिये जाने का आग्रह किया | इसके साथ ही स्टैंड अप ऋण योजना मे ग्रामीण बस सेवा के अंतर्गत निर्धारित रूटों पर बैंको से ऋण दिये जाने का आग्रह भी किया गया | उन्होने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गठित लघु कुटीर उद्यम बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि सखी मंडलों को ज्यादा से ज्यादा ऋण का संवितरण सुनिश्चित किया जाए क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे products को सीधे राज्य सरकार द्वारा purchase किया जा रहा है जिससे उन उद्यमों कि viability पर कोई संदेह नहीं है | इसके साथ ही उन्हीने सखी मंडलों को दिये जाने वाले ऋण के documentation में राज्य सरकार द्वारा stamp duty waive किये जाने की बात बताई | उन्होने DFS के संयुक्त सचिव से बैंक शाखाओं को खोले जाने मे

शिथिलता बरते जाने के मुद्दे को बैंको के head offices के साथ उठाए जाने का सुझाव दिया | इसके साथ ही उन्होने digital transaction को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा सखी मंडलों को 1 लाख smart phones दिये जाने कि बात बताई | साथ ही recovery के issue पर बोलते हुए उन्होने सभी बैंको को DCs के साथ coordinate कर SARFAESI के अंतर्गत बड़े defaulters के properties को attach किए जाने का प्रयास करने कि सलाह दी जिसके लिए उन्होने सचिव, expenditure श्री सतेन्द्र सिंह से सभी जिलों के DCs को समुचित instruction दिये जाने का भी निदेश दिया |

व्यवसाय सत्र (Business Session): अध्यक्ष के आदेशानुसार, मुख्य प्रबंधक, SLBC, श्री दीप शंकर द्वारा व्यवसाय सत्र की कार्यवाही शुरू करते हुए सर्वप्रथम दिनांक 12.05.2017 को आयोजित 59वी एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत की संपुष्टि सभा द्वारा कराई गयी |

तत्पश्चात श्री दीप शंकर ने एसएलबीसी की 60वीं बैठक में चर्चा किए जाने वाले बिन्दुओं को क्रमवार प्रस्तुत किया।

राज्य सरकार से संबंधित मामले:

नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना:

SLBC द्वारा राज्य सरकार से पिछली बैठक के दौरान तत्कालीन प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्री एन एन सिन्हा द्वारा दिये गए जानकारी पर वर्तमान वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया, जिसपर सरकार द्वारा यह बताया गया कि यह मामला अभी भी राज्य सरकार के विचारधीन है और इसमे जल्द ही प्रगति अपेक्षित है | **(Action: राज्य सरकार)**

वित्तीय शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम मे शामिल करने के संबंध मे :

इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक श्री अमित सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों मे नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कराया जाना है, जिसपर अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त श्री अमित खरे ने इसे राज्य मे जल्द लागू कराये जाने का आश्वाशन दिया | **(Action: राज्य सरकार)**

DCC/DLCC कि बैठक RBI द्वारा जारी किए गए calendar के अनुसार नियत तिथि पर किया जाना:

अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त श्री अमित खरे द्वारा DCC/DLRC कि बैठक सभी जिलों में एक ही नियत तिथि पर कराये जाने कि संभावना पर RBI के सहायक महाप्रबंधक श्री अमित सिन्हा ने कहा कि चूंकि कई अधिकारी जो विभिन्न जिलों मे इन बैठकों को attend

करने के लिए नामित किए जाते हैं, उनके लिए सभी जगहों पर एक ही दिन अपनी उपस्थिती दर्ज कराना संभव नहीं हो पाएगा | श्री खरे के सभी प्रखंडों मे BLBC की बैठक एक ही नियत दिन करने के सुझाव का सभा मे उपस्थित सभी हितधारकों ने स्वागत किया |

(Action: राज्य सरकार)

इसके पश्चात बैंको से संबन्धित तीन मुद्दों , जिसमे RSETI भवनों के निर्माण, RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का credit linkage एवं Stand Up India ऋण योजना की प्रगति की चर्चा की गई और सभी बैंकों से इसपर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया |

(Action: सभी बैंक एवं RSETI से सम्बंधित बैंक-PNB, BOI,Allahabad बैंक एवं SBI)

जमा, क्रेडिट एवं ऋण-जमा अनुपात

इस संबंध मे यह बतलाया गाय कि राज्य के बैंकों के जमास्तर में वर्ष-वार उत्तरोतर वृद्धि दर्ज की जा रही है परंतु ऋण संवितरण के स्तर में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की रफ्तार कम होने के कारण राज्य मे ऋण-जमा अनुपात मे लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है |

इस विषय पर मुख्य प्रबन्धक श्री दीप शंकर ने आगे जानकारी देते हुए बतलाया कि दिनांक 10.08.2017 को ACP एवं ऋण-जमा अनुपात के sub-committee की बैठक मे निर्णय लिया गया है कि जिन बैंकों एवं ज़िले का जमा अनुपात 30% एवं 40% से नीचे चला गया है, उन बैंको को विशेष Monitorable action plan बनाकर योजनाबद्ध तरीके से इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। **(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

कृषि ऋण

कृषि ऋण में आई गिरावट के मद्देनज़र हुए विचार-विमर्श में सभी बैंको द्वारा ज्यादा से ज्यादा मियादी कृषि ऋण के संवितरण पर ध्यान देने को कहा गया | इसी क्रम मे RBI द्वारा पिछले तीन तिमाहियों से agriculture sub-committee की बैठक नहीं किए जाने का मामला भी उठाया गया | **(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

वार्षिक ऋण योजना के आधार पर वर्ष 2016-17 की उपलब्धि की समीक्षा

श्री दीप शंकर ने बतलाया कि पिछले वर्ष के प्रथम तिमाही की तुलना मे इस वर्ष के प्रथम तिमाही मे कुल ऋण संवितरण मे वृद्धि हुई है परंतु पूरे राज्य में कुल ऋण का o/s पिछले quarter की तुलना मे काफी कम हुआ है । इस पर विकास आयुक्त ने जिलावार हुई उपलब्धि के अनुसार कम achievement वाले जिलों से यह जानने का प्रयास किया कि वहाँ किन कारणों से उपलब्धि अन्य जिलों की तुलना मे अपेक्षाकृत कम रही है | कुछ LDMs द्वारा उचित कारणों को न बताए जाने पर BOI के महाप्रबंधक श्री एस॰ के॰ मुखर्जी ने असंतोष व्यक्त किया और सभी LDMs से credit को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने को कहा | DFS के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा ने भी LDMs को local chamber of commerce के पदाधिकारियों

से एवं DCs से लगातार meeting कर नए avenues को तलाशने का सुझाव दिया ताकि बैंको द्वारा उस जिले मे ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह किया गया कि आरंभ से ही शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा मे प्रयास किया जाए।

(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)

KCC का Rupay कार्ड मे conversion

DFS के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा द्वारा co-operative बैंक से उनके यहाँ KCC के Rupay कार्ड मे conversion कि स्थिति पूछे जाने पर बैंक के एमडी श्री प्रफुल्ल रंजन ने बताया कि उनके यहाँ eligible 21000 KCC खातों मे से लगभग 5000 खातों मे conversion की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शेष बचे खाते Sept के अंत तक कर लिए जाने का आश्वशन दिया | अन्य बैंको से भी यह कार्य जल्द पूर्ण कर लिए जाने का आग्रह किया गया |

(Action: सभी बैंक एवं Co-operative बैंक)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

श्री दीप शंकर ने इस संबंध मे कहा कि एसएलबीसी द्वारा PMFBY से संबन्धित सभी सूचनाओं एवं govt. notifications को सभी बैंको को बार-बार भेजने एवं आगाह किए जाने के बावजूद सभी eligible loanee के खातों मे insurance की सुविधा नहीं प्रदान की गयी है, जिसे बैंको द्वारा अविलंब पूरा किया जाना चाहिए | **(Action: सभी बैंक)**

सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई)

श्री दीप शंकर ने इस संबंध मे कहा कि इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में MSME sector में बैंको ने अच्छा कार्य किया है और पूरे वित्तीय वर्ष के target के विरुद्ध 50% से ज्यादा की उपलब्धि हो गई है | इसके साथ ही कुल MSE sector में Micro sector का ऋण प्रतिशत पिछ्ले वर्ष की तुलना में 54.23% से बढ़कर 57.45% हो गया है | परंतू रु 2 करोड़ तक के कुल लगभग eligible 4.20 लाख MSE खातों में से केवल 0.99 लाख खातों में ही CGTMSE coverage लिया गया है | कुछ बैंको द्वारा यह कहे जाने पर कि इनमे कई खाते collateral security लेकर sanction किये गए हैं और इनमे CGTMSE coverage की जरुरत ही नहीं है, श्री मदनेश मिश्रा ने SLBC को सभी बैंको से इस सम्बन्ध में fresh रिपोर्ट लेने की सलाह दी ताकि बैंको द्वारा केवल वैसे खातों के विरुद्ध CGTMSE coverage की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके जो बैंक के स्वीकृति शर्तों के अधीन इसके लिए पात्र हैं | RBI के सहायक महाप्रबंधक श्री अमित सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंको द्वारा MSME के restructure/rehabilitation के लिए गठित कमिटि की नियमित बैठक नहीं हो पाती है, जिससे कई सारे stressed accounts का समय रहते ध्यान नहीं दिया जा पाता है |

(Action: SLBC एवं सभी बैंक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

श्री दीप शंकर ने इस संबंध मे कहा कि इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में झारखण्ड राज्य में मुद्रा योजना के तहत ऋण के संवितरण में काफी प्रगति हुई है और पिछले वित्तीय वर्ष के तीन तिमाहियों के दौरान जहाँ मुद्रा ऋण केवल 750 करोड़ रु के आस पास वितरित किया गया था वही इस बार केवल एक तिमाही में ही यह आंकड़ा रु 836 करोड़ का है | झारखण्ड सरकार के वित्त सचिव श्री सतेन्द्र सिंह ने SLBC से मुद्रा योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंको को जिलावार दिये गए target की जानकारी राज्य सरकार को देने का निर्देश दिया | श्री अमित खरे ने आगामी गरीब कल्याण मेला के दिन मुद्रा योजना के अंदर और भी अधिक अच्छा performance करने की अपील की और सभी बैंको से प्रथम तिमाही में ऋण प्राप्त लाभार्थियों का मेला में उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा | **(Action: SLBC एवं सभी बैंक)**

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव श्री अमित खरे एवं DFS के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा दोनों ने स्टैंड अप इंडिया ऋण में उपलब्धि बजट से काफी कम रहने पर असंतोष व्यक्त किया | SLBC द्वारा सभा में उपस्थित सभी बैंकों से यह आग्रह किया गया कि SUI योजना के तहत स्वीकृत किये गए सभी ऋणों को पोर्टल पर अविलम्ब upload किया जाये ताकि इस sector में हुई वास्तविक प्रगति का पता चल सके |

इसके साथ ही ग्रामीण रूटों पर प्रस्तावित बस सेवा के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को इस योजना के तहत ऋण देने का निर्देश दिया गया | **(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

शिक्षा ऋण

DFS के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा ने कहा कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर भी SC/ST/OBC विद्यार्थियों के लिए information दिया जाने का प्रावधान है, अतः उनके द्वारा NSDL के साथ दिनांक 24.08.20.17 को होने वाली बैठक के दौरान सभी SLBC conveners को User ID और Password दिलाने का प्रयास किया जायेगा ताकि यह information सभी राज्यों को मिल सके जिससे प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अपने-अपने performance का आकलन कर सके | RBI के क्षेत्रीय निदेशक, श्री पैट्रिक बारला ने SLBC द्वारा राज्य के SC/ST/OBC विद्यार्थियों के लिए बनाये गए पोर्टल का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाने का सुझाव दिया | विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव श्री अमित खरे ने SLBC को इस पोर्टल से संबंधित banners/posters बनवाने का सुझाव दिया ताकि राज्य सरकार इसे शिक्षण संस्थाओं में display कर सके जिससे इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके | RBI के सहायक महाप्रबंधक श्री अमित सिन्हा ने सुझाव दिया कि जन संपर्क विभाग के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में जो बड़े screens लगाये गए हैं, उनपर इस पोर्टल से संबंधित जानकारी display किया जाये | **(Action: राज्य सरकार, SLBC एवं सभी बैंक)**

ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह

श्री दीप शंकर ने सभा को जानकारी देते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में झारखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को दिये गए ऋण में वृद्धि दर्ज की गई है, परंतू महिलाओं को दिये जा रहे ऋण में काफी कमी आयी है | इसपर महिलाओं के SHGs को और ज्यादा ऋण दिये जाने का सुझाव दिया गया | **(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

इस विषय पर SLBC द्वारा इस वित्तीय वर्ष में हुई कुल उपलब्धि जिनमे नाबार्ड एवं JSLPS द्वारा promoted SHGs भी शामिल हैं, का ब्यौरा सभा को दिया गया | JSLPS के CEO श्री परितोष उपाध्याय ने खासकर BOI एवं SBI में लंबित पड़े आवेदनों का जिक्र किया और संबंधित बैंको से जल्द से जल्द इन ऋणों को स्वीकृत कराकर वितरित किये जाने का अनुरोध किया | विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव श्री अमित खरे ने गरीब कल्याण मेला के दिन अधिकतम SHGs का ऋण संवितरित किये जाने का निदेश दिया |

(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)

प्रधानमंत्री जन धन योजना

NABARD के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस. मंडल द्वारा यह बताये जाने पर कि co-opertaive बैंक को NABARD द्वारा दिये गए 1000 micro ATMs से संबंधित जानकारी SLBC के book में उपलब्ध नहीं है, SLBC द्वारा यह बताया गया कि अगली बार से co-opertaive बैंक द्वारा भी SLBC के पोर्टल पर सारे information देने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि उनके बैंक से संबंधित सभी आंकडो की जानकारी सभा को हो सके | अभी co-opertaive बैंक द्वारा कुछ parameters की जानकारी SLBC को mail के through उपलब्ध करायी जा रही है |

DFS के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा ने जानना चाहा कि PMJDY खातों में mobile seeding का प्रतिशत aadhar seeding की तुलना में काफी कम क्यों है, इसपर झारखण्ड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री बृजलाल ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में connectivity issue और गरीबी की वजह से कई लोगों के पास mobile उपलब्ध नहीं है | RBI के सहायक महाप्रबंधक श्री अमित सिन्हा ने बताया, कि RBI द्वारा कराये गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि झारखण्ड में कई लोग Cyber crime की वजह से mobile no. share किये जाने में बहुत interested नहीं होते है | BOI , जमशेदपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री अलोक प्रकाश यादव ने कहा कि कई वैसे लोग जिनके पास mobile नहीं है और उनका एक से ज्यादा खाता है, तो इसका mobile seeding के कम रहने में दुहरा प्रभाव पड़ता है | इन कठिनाइयों के बावजूद श्री मदनेश मिश्रा ने mobile seeding को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक प्रचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया | श्री अमित खरे ने कई पिछड़े जिलों का हवाला देते हुए यह बताया कि वहाँ mobile seeding का प्रतिशत अन्य कई जिलों की तुलना में बेहतर है , अतः सभी बैंको एवं SLBC के संयुक्त प्रयास से इसमें अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है |

(Action: SLBC, co-opertaive बैंक, अन्य सभी बैंक एवं सभी LDMs)

अटल पेंशन योजना (APY)

श्री दीप शंकर ने सभा को जानकारी देते हुए कहा कि PFRDA द्वारा SLBC की बैठकों में APY की उपलब्धियों पर व्यापक चर्चा करने का निर्देश दिया गया है , अतः सभी बैंकों द्वारा इस sector में हुई उपलब्धि की जानकारी SLBC को मासिक आधार पर प्रेषित की जाये | इसके लिए पूर्व में निर्धारित budget ही मान्य होगा, जिसमे सभी PSUs एवं कुछ चुनिन्दा Pvt banks यथा -Axis, ICICI, HDFC को 70 APY cases प्रति शाखा प्रति वर्ष, RRBs को 50 a/cs per branch/per year तथा Cooperative Bank को 20 a/cs per branch/per year का target दिया गया था |

(Action: SLBC एवं सभी बैंक)

बैंक शाखाओं का खोला जाना

श्री दीप शंकर ने सभा को जानकारी देते हुए कहा कि आरबीआई के बैंकिंग आउटलेट के संबंध मे नए दिशानिर्देश बैविवि. बीसी.बीएपीडी.सं.69/22.01.001/2016-17 दिनांक 18 मई 2017 के अनुसार झारखण्ड में चिन्हित किये गए 137 गाँवों में 128 गाँव मे बैंक की शाखा या FIXED LOCATION BC खुल चुके हैं। बाकी बचे 9 गाँवों में शाखा का खोला जाना अथवा BC की नियुक्ति लंबित हैं, जिनमे Central Bank of India के 2 centres, United Bank of India के 3 centres, Bank of India, Axis Bank, Canara Bank एवं Vijaya Bank का 1-1 centre शामिल है | सभी सम्बन्धित बैंको द्वारा दिनांक 30.09.2017 के पूर्व या तो शाखा खोल लिए जाने अथवा fixed location BC की नियुक्ति कर लिए जाने का आश्वाशन सभाध्यक्ष को दिया गया |

(Action: CBI, UBI, BOI, Canara Bank, Axis Bank एवं Vijaya Bank)

इसी क्रम में आगे हुई चर्चा में RBI के द्वारा 2000 से कम की जनसँख्या वाले गाँवों में भी part time banking outlet दिये जाने की बात कही गई | RBI द्वारा 2000 से कम जनसँख्या वाले सभी गाँवों में 31.12.2017 तक fixed location BC नियुक्त किये जाने की बात पर श्री मदनेश मिश्रा ने ग्राम डाक सेवकों को BC के रूप में बहाल किये जाने की संभावना तलाशने का बैंको को सुझाव दिया | RBI के सहायक महाप्रबंधक श्री अमित सिन्हा ने राज्य के अंदर कार्य कर रहे Small Finance Bank-उज्जीवन और उत्कर्ष एवं India Post के data को SLBC के agenda book में शामिल किये जाने की सलाह दी | उन्होंने स्कूली बच्चों के खाता खोलने में कई जगह minimum balance/service charge लिए जाने का मुद्दा भी उठाया, जिसके लिए SBI को विशेष रूप से इसकी समीक्षा करने को कहा गया |

(Action: SLBC, SBI एवं सभी बैंक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखण्ड

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

Municipal Administration के निदेशक श्री आशीष सिंघमार ने सभा को बताया कि CLSS के अंतर्गत PMAY स्कीम एवं NULM के अंतर्गत बैंको द्वारा काफी कम ऋण दिया गया है और इसमें अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है | उन्होंने interest subsidy claim में बैंको द्वारा देरी किये जाने और इन schemes के अंतर्गत बैंको में पड़े लंबित आवेदनों की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट कराया | इसके साथ ही उन्होंने मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत किये गए ऋण खातों के NULM scheme में conversion की बात भी बताई |

(Action: HUDCO, NHB, राज्य सरकार, सभी बैंक एवं सभी LDMs)

RSETI एवं FLCC

श्री परितोष उपाध्याय ने सभा को RSETI construction के बाबत विभिन्न बैंको के द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और RSETI द्वारा trained अभ्यर्थियों को लोन दिये जाने की बात कही | RBI के क्षेत्रीय निदेशक, श्री पैट्रिक बारला ने बैंको से कहा कि ज्यादा से ज्यादा RSETI द्वारा trained अभ्यर्थियों को लोन दिये जाएँ | **(Action: सभी बैंक)**

विविध कार्य सूची

1. SLBC द्वारा ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव के पत्रांक 10-PMAY-G-23/2017-Gra 4171 दिनांक 03.08.2017 के द्वारा PMAY-G से संबंधित उठाये गए कतिपय मुद्दों की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट कराया गया और सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह किया गया कि वे अपने शाखाओं को समुचित निर्देश दे ताकि इन मुद्दों पर उचित एवं त्वरित कार्यवाही हो | इन मुद्दो में प्रमुख रूप से बैंको द्वारा पेमेंट से इंकार करना, छोटे-छोटे टुकड़ों में पेमेंट करना, FTO पेमेंट में देरी, खातो के verification में देरी, जन धन खातों को सामान्य खातों में परिवर्तन करने में कठिनाई, PMAY-G के लिए दिये गए सहायता राशि से ऋण की कटौती इत्यादि शामिल है | **(Action: सभी बैंक)**

2. SLBC द्वारा सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि e-pos machines का data जिसमे उनके यहाँ किये गए requisition और install किये गए e-pos machines की जानकारी हो, वह SLBC को उपलब्ध कराया जाये | सचिव वित्त-सह-योजना, झारखंड सरकार, श्री सतेन्द्र सिंह ने इस विषय पर और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में e-merchant managers एवं सभी प्रखंडों में e-block managers की नियुक्ति की गई है जिनका दायित्व सभी businessmen से मिलकर उनके यहाँ e-pos machines install किये जाने की संभावना तलाशना है और उनके जरुरत के हिसाब से उनसे आवेदन लेकर बैंको को देना है ताकि digital transaction को बढ़ावा दिया जा सके | इस सम्बन्ध में उन्होंने सभी LDMs से e-merchant managers एवं e-block managers से co-ordinate कर ज्यादा से

ज्यादा e-pos machines राज्य में लगवाए जाने का सुझाव दिया | उन्होंने राज्य के कुछ गाँवों को digital village बनाने के लिए बैंको से सहयोग देने का निर्देश दिया | श्री मदनेश मिश्रा ने digital transaction को बढ़ावा देने हेतु Bhim App, Bharat QR code, UPI इत्यादि तरीकों को अपनाने की सलाह दी | **(Action: सभी बैंक)**

व्यवसाय सत्र की समाप्ति के पश्चात NABARD के प्रतिनिधि श्री जे एस उपाध्याय द्वारा e-shakti एवं SHGs के digitization पर एक presentation सभा में दिया गया |

सभा के अंत में यूनाइटेड बैंक के उप महाप्रबंधक श्री एस. के. सिन्हा ने सभी गणमान्य अतिथियों, प्रतिभागियों एवं मीडिया का धन्यवाद ज्ञापन किया । तत्पश्चात एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री प्रसाद जोशी ने सभी का धन्यवाद करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा की ।

(प्रसाद जोशी)
महाप्रबंधक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
BOI
झारखण्ड